[श्री इकबाल सिंह]

सरकार पूरे देश में शिशु केंद्र स्थापित करे और ऐसी व्यवस्था करे कि यदि किसी दंपति को नवजात शिशु कन्या की जरूरत नहीं है तो वह अपने उन बच्चों को इन केंद्रों में रख सकें और सरकार उनका लालन पालन कर सके । मैडम, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि महिलाओं में भ्रूण के सेक्स संबंधी परीक्षणों पर रोक लगाई जाए और राज्य सरकारों को इस संबंध में कारगर कदम तथा सख्त से सख्त कदम उठाने संबंधी निर्देश जारी किए जाएं । इस बारे में शीघ्र ही एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए जो अभी तक नहीं बन सकी है। "मनपसंद संतान प्राप्त करें" इस प्रकार के विज्ञापनों पर पाबंदी लगाई जाए और प्राइवेट चिकित्सा केंद्रों के विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई करे ताकि लड़कियों की इस प्रकार हत्या करने पर रोक लगाई जा सके । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): Madam,...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I take the name of Mrs. Chandra Kala Pandey, Mr. Agarwal and the rest of us who are associating themselevs with what has been said by Shri Iqbal Singh.

SHRI SATISH AGARWAL: Madam, just one second I will take.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have got other names now.

SHRI SATISH AGARWAL: Madam, some incentive should be given to those parents who get themselves sterilised after two children. It would be an encouragement to them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Whether two sons or two daughters? Now, Shri Raj Nath Singh.

Three Language formula of Uttar Pradesh

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं इस सदन और शासन का ध्यान एक अत्यंत गम्भीर प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और ऐसे विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति और भारत के दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है । महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिभाषा सूत्र में से संस्कृत को निकाल दिया है। पहले यह व्यवस्था थी कि त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की पढ़ाई करने वाला छात्र प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी ले सकता था, दूसरी भाषा या विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी ले सकता था और तीसरी भाषा वह थी, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में आती हैं, हिन्दी को छोड़ कर 1 तो उसमें से छात्र संस्कृत भी ले सकता था, उर्दू भी ले सकता था।

महोदया, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने शब्दावली में, शासनादेश की शब्दावलि में परिवर्तन करके तीसरी भाषा में यह कर दिया है कि अब आधुनिक भारतीय भाषाओं में से हिन्दी को छोड़कर कोई भाषा छात्र ले सकता है। परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उत्तर प्रदेश में अब 95 प्रतिशत छात्र उर्दू लेने के लिये बाध्य होंगें, यानि संस्कृत की पढ़ाई करने वाले छात्र चाहते हुए भी संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं कर सकेंगे और परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि हजारों-हजार की संख्या में संस्कृत के अध्यापक पूरी तरह से बेरोजगार हो जायेंगे । बहुत भारी संख्या में उर्दू अध्यापकों को नियुक्त करना पड़ेगा, जिससे शासन के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी पड़ेगा।

महोदया, मैं मानता हूं कि उर्दू हिन्दुस्तानी जुबान है, उर्दू का भी विकास होना चाहिए, उर्दू का भी सवर्द्धन होना चाहिए । इसको भी रोजगार के साथ जोड़ा जाना चाहिय, लकिन संस्कृत की कीमत पर नहां । संस्कृत वास्तव में हमारे देश की गौरवशाली भाषा है, वह भारत के गौरवशाली अतीत के साथ जुड़ी हुई भाषा है। मैं मानता हूं संस्कृत आम जीवन की भाषा नहां बन पाई है, लेकिन संस्कृत को आम जीवन की भाषा तभी बनाया जा सकता है,

जबकि उसको रोजगार के साथ जोड़ने की कोशिश हम करेंगे।

महोदया, मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वाशिंगटन में विश्व के वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ था। सारे विश्व के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत थे कि कम्प्यूटर की क्षमता बढ़ाने के लिये सबसे साइंटिफिक कोई लेंगवेज हो सकती है, तो वह संस्कृत हो सकती है। संस्कृत का जहां पर दिन ब दिन विकास होना चाहिये, वहां उत्तर प्रदेश से संस्कृत की उपेक्षा की जा रही है।

उपसभापति महोदया, हमारा यह भी अनुरोध है आपके माध्यम से भारत सरकार से वह कि वह इसमें हस्तक्षेप करें, ताकि संस्कृत की वहां पर उपेक्षा न होने पाये। साथ ही, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए तीसरी भाषा के रूप में, जैसे हमारी भाषाएं हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, मलायलम है, कन्नड़ है, दक्षिण भारतीय भाषाओं को भी उत्तर प्रदेश में पढ़ाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

महोदया, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बार-बार सीना ठोक कर इस बात को कहती है कि उर्दू को रोजगार के साथ जोड़ दिया है और तर्क यह दिया जाता है कि शान्ति सुरक्षा बल जोकि उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रही है, उसमें उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि उर्दू भाषा जानते हैं। महोदया, इस आप स्वयं यह कल्पना कर सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की अजीबो-गरीब स्थिति इस से पैदा हो जायेगी। पुलिस बल के अन्दर अभी आक्रोश है, आगे जिस प्रकार का आक्रोश होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। संस्कृत की उपेक्षा के कारण छात्रों में, शिक्षकों में, बुद्धिजीवियों के अन्दर एक गम्भीर आक्रोश पैदा हुआ है। वहां के शिक्षक संगठनों ने, वहां के बुद्धिजीवियों ने आन्दोलन की धमकी दी है। अतः मैं आप के माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार इस में हस्तक्षेप करें।

श्रीमती मालती शर्मा (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, माननीय राजनाथ जी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए, मैं इसी के समर्थन में एक बात कहना चाहती हूं कि कुछ समय तक उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में रहने का मुझे असवसर मिला है। उस समय हमारे सामने यह प्रकरण आया था। उसका एक ही उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूं।

उपसभापति: इस वक्त समय नहीं है दूसरी दफा बताएइगा।

I have other names which are listed over here.

श्रीमती मालती शर्मा: केवल एक जानकारी देना चाहती हूं। उस समय उर्दू के शिक्षकों की भरती के संबंध में एक प्रकरण मेरे पास आया था। हमने जानकारी की तो पता लगा कि उर्दू पढ़ने वाले लोग नहीं थे और उर्दू के अध्यापक घर बैठे तनख्वाह ले रहे थे। हमने कहा कि अगर विद्यार्थी हों तब तो उर्दू के अध्यापक भरती की जाए, अन्यथा पुराने अध्यापक ही घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, नए अध्यापक भरती क्यों किए जाए। इस लिए अध्यापकों की भरती से पहले एक सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। जो बात इन्होंने रखी है इस का मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूं।

1.00 P.M.

Acute Water Scarcity in Saurashtra, Kutch and Northern Gujarat

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR (Gujarat): Madam, I take this opportunity to invite the attention of this august House and the Government to the dark shadow of drought and water scarcity which is lengthening over several parts of Kutch, Saurashtra and North Gujarat, affecting 20 million people of the State. Recurring drougts, inadequate and irregular rainfall have been the bane of these areas, and the lack of rains in the last monsoon not only affected the agricultural operations and yield but has also resulted in acute scarcity of drinking water and fodder for the cattle. With summer now in full swing, the cup of